

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग). गुजरात सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के समक्ष रख दी जाएगी ।

कच्छ में लिग्नाइट पर आधारित बिजली के उत्पादन के बारे में गुजरात से योजना

268. श्री धर्म सिंह भाई पटेल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए कच्छ में लिग्नाइट पर आधारित एक बिजली संयंत्र योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) उनको कितने मेगावाट की क्षमता होगी तथा उस पर कितनी धन-राशि खर्च होगी ; और

(घ) उस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :

(क) जी, हां ।

(ख) दिसम्बर, 1977 में ।

(ग) प्रस्तावित ताप विद्युत् केन्द्र की 55-55 मेगावाट की दो यूनिटों की क्षमता 110 मेगावाट है । इसकी अनुमानित लागत 56.50 करोड़ रुपये है ।

(घ) तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए इस प्रस्ताव की जांच केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण में की जा रही है ।

Problems of Jute Industries

269. SHRI UGRASEN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he had recently discussed problems of jute industry and adequate supplies of raw jute to mills throughout the year so that the interests of both industry and workers are protected; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI): (a) and (b). Minister of Industry visited Calcutta on 12th January, 1978 and held a series of meetings regarding the problems faced by the jute industry with the representatives of the Government of West Bengal, jute industry, trade unions, etc. In these meetings mainly the following issues were discussed:—

1. Availability of raw jute in the short-term and measures required for unearthing the hoarded stocks.

2. Suggestion of jute industry to introduce production cut in jute industry, and its impact on labour,

3. The role of Jute Corporation of India for ensuring a remunerative return to growers as well as adequate supplies of raw jute to mills at economic prices.

Transport facilities in Ladakh

270. SHRIMATI PARVATI DEVI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state: The steps Government propose to take to improve the means of road transport in Ladakh?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): Out of 1103 Kms of roads planned to be financed by the Central Government 1050 Kms have been constructed so far. The State Govt. is also developing roads as part

of State Plans and is reported to have spent Rs. 128.36 lakhs during 1976-77 and 1977-78.

As for Road Transport, the State Govt. are reported to have taken a number of measures including issue of stage carriage permits to Ladakhis for operation within Ladakh; issue of licences for 18 public carriers and 40 jeep taxis to ply as private carriers, maintenance of 12 buses by State Road Transport Corporation for passenger transport in Ladakh and grant of permits for 43 jeep taxis for plying between Srinagar and Leh.

Promotion of Industries in J. & K.

271. SHRIMATI PARVATI DEVI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state what steps have been taken for the promotion and development of industries in Jammu and Kashmir State under the Rural Industrial Project Programme sponsored by the Central Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI): Under the Rural Industries Projects Programme sponsored by the Central Government 4 districts of J & K viz., Anantnag, Baramulla, Doda and Kathua have been covered so far. Under this scheme Central assistance is given to the State Government for meeting the full expenditure on the establishment of the project and for organising promotional schemes like Training Programmes and Common Facilities Services Centres. Assistance by way of loan is also provided to the State Government for re-advancing the same at a very low rate of interest to the entrepreneurs for starting industries in the Project Areas.

प्रक्षेपणास्त्रों के निर्माण में आत्मनिर्भरता

272. श्री हुकम चन्द कठुवाय : क्या रक्षा मंत्री 30 नवम्बर, 1977 के अतारंकित प्रश्न संख्या 2050 के उत्तर

के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए प्रक्षेपणास्त्रों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य में अभी और क्या-क्या कार्यवाही की जानी शेष है ; और

(ख) छापामार युद्धकला में भारत को अब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाने की आशा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० शेर सिंह) : (क) हमारी सशस्त्र सेनाएं जिन राकेटों/प्रक्षेपणास्त्रों का उपयोग कर रही हैं उनमें से कुछ पहले ही देश में बनाए जा रहे हैं। सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रयोग के लिए चुने गये कुछ और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए प्रक्षेपणास्त्र बनाने के प्रयत्न जारी हैं। इस कार्यक्रम में सम्बद्ध आधुनिकतम संचार तथा रेडार प्रणालियों का विकास एवं उत्पादन सम्मिलित होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कार्रवाई को जा रही है उसमें अनुसंधान तथा विकास और चरणबद्ध ढंग से उत्पादन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। इस पर लगभग 7 से 10 वर्ष का समय लगने की आशा है। चूंकि इस क्षेत्र में बहुत ही आधुनिकतम टेक्नालाजी आती है इसलिए समय का मोटा सा अनुमान ही लगाया जा सकता है। परन्तु सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर प्रक्षेपणास्त्रों के प्रयोग तथा साथ ही संघटकों और इस तरह की प्रणालियों के लिए अपेक्षित उप-प्रणालियों के सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में काफी समय लगेगा।

(ख) हमारे कुछ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में अफसरों, जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों और अन्य रैंकों को गुरिला युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है। परन्तु